

## सूचना

**स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर**  
प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, 'सी'-स्कीम,  
जयपुर-302 005

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अंशधारकों की 52वीं वार्षिक साधारण सभा महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुंशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर - 302015 में शुक्रवार दिनांक 7 जून 2013 को पूर्वाह्न 11:30 बजे ( भारतीय मानक समय ) आयोजित की जावेगी जिसमें 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता, इसी अवधि में बैंक के कार्यकरण एवं क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल के प्रतिवेदन तथा तुलन-पत्र व लेखों के सम्बन्ध में संपरीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार कर पारित किया जायेगा।

बैंक के अंशधारकों का रजिस्टर शुक्रवार दिनांक 31 मई, 2013 से गुरुवार दिनांक 6 जून, 2013 तक (दोनों दिन मिलाकर) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की वार्षिक साधारण सभा हेतु बन्द रहेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

दिल्ली  
दिनांक: 06 मई, 2013

बी. श्रीराम  
प्रबन्ध निदेशक

## NOTICE

**STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR**  
Head Office, Tilak Marg, 'C'-Scheme,  
Jaipur-302 005

NOTICE is hereby given that the Fifty-second Annual General Meeting of the Shareholders of State Bank of Bikaner and Jaipur will be held in the **Maharana Pratap Auditorium, Bharatiya Vidya Bhavan, K. M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., Jaipur - 302015 on Friday, the 7<sup>th</sup> June, 2013 at 11.30 A.M. (Indian Standard Time)** to discuss and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts for the period 1<sup>st</sup> April, 2012 to 31<sup>st</sup> March, 2013.

The register of shareholders of the Bank shall remain closed from Friday, the 31<sup>st</sup> May, 2013 to Thursday, the 6<sup>th</sup> June, 2013 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2013.

By Order of the Board

Delhi  
Dated: 06<sup>th</sup> May, 2013

**B. Sriram**  
Managing Director

## विषय-सूची CONTENTS

उल्लेखनीय तथ्य	03
Highlights	03
निदेशक मण्डल	04
Board of Directors	04
निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	06
Directors' Report	07
बासेल-II प्रकटीकरण	78
Basel-II Disclosures	79
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	116
Auditors' Report	117
तुलन-पत्र	120
Balance Sheet	120
लाभ-हानि खाता	122
Profit & Loss Account	122
अनुसूचियां	124
Schedules	124
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	136
Principal Accounting Policies	137
खातों पर टिप्पणियाँ	150
Notes on Accounts	151

## उन्नति का एक दशक 2004-2013 A Decade of Progress 2004-2013

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

संकेतक <i>Indicators</i>	पूँजी एवं आरक्षितियां <i>Capital &amp; Reserves</i>	कुल व्यवसाय <i>Total Business</i>	परिचालन लाभ <i>Operating Profit</i>	निवल लाभ <i>Net Profit</i>	शाखाओं की संख्या <i>No. of Branch- es</i>	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय <i>Average Business per Employee</i>	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹लाख में) <i>Net Profit per Employee (₹In lakh )</i>
मार्च <i>March</i> 2004	1148.57	25457	681.35	301.52	812	1.70	2.44
मार्च <i>March</i> 2005	1297.68	31294	729.64	205.65	824	2.20	1.69
मार्च <i>March</i> 2006	1405.66	37790	481.03@	145.03	832	2.77	1.20
मार्च <i>March</i> 2007	1653.71	49246	679.20@	305.80	844	3.56	2.57
मार्च <i>March</i> 2008	1713.21	59427	661.18@	315.00	850	4.45	2.73
मार्च <i>March</i> 2009	2046.47	69312	892.84@	403.45	860	5.55	3.55
मार्च <i>March</i> 2010	2417.40	81622	903.73@	455.16	861	6.28	3.96
मार्च <i>March</i> 2011	2850.81	95596	1140.25@	550.88	902	7.51	4.84
मार्च <i>March</i> 2012	4164.88	111558	1489.61@	652.03	950	8.27	5.42
मार्च <i>March</i> 2013	4764.13	130590	1712.87@	730.24	1037	9.00	5.91

@ निवेशों के मूल्यांकन के लिए भारिबैं द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को दृष्टिगत करते हुए।  
*Keeping in view revised RBI guidelines on valuation of investments.*

## उल्लेखनीय तथ्य HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

	2011-12	2012-13
कुल व्यवसाय अन्तर-बैंक जमाओं सहित <b>Total Business including inter-bank deposits</b>	111558	130590
जमाराशियाँ <b>Deposits</b>	61572	72116
कुल अग्रिम <b>Total Advances</b>	49986	58474
अग्रिम (निवल) <b>Advances (Net)</b>	49244	57535
निवेश (निवल) <b>Investments (Net)</b>	16669	20146
निवल लाभ <b>Net Profit</b>	652.03	730.24
जमाओं की लागत <b>Cost of Deposits</b>	6.85%	7.13%
अग्रिमों पर आय <b>Yield on Advances</b>	11.51%	11.64%
निवल ब्याज अन्तर <b>Net Interest Margin</b>	3.70%	3.62%
प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षितियाँ <b>Paid-up Capital &amp; Reserves</b>	4164.88	4764.13
प्रति अंश आय (₹ में) <b>Earning per Share (in ₹)</b>	95.05	104.32
प्रति अंश पुस्तक मूल्य (₹ में) <b>Book Value per Share (in ₹)</b>	594.98	678.74
पूँजी पर्याप्तता अनुपात <b>Capital Adequacy Ratio</b>	बासेल-I के अनुसार <b>As per Basel-I</b>	12.81%
	बासेल-II के अनुसार <b>As per Basel-II</b>	13.76%
लाभांश दर <b>Dividend Rate</b>	145%	161%
सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ <b>Gross Non Performing Assets</b>	1651.47	2119.49
सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ प्रतिशत <b>Gross NPA %</b>	3.30%	3.62%
निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ प्रतिशत <b>Net NPA %</b>	1.92%	2.27%
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम <b>Advances to Priority Sectors</b>	17690	20807
कृषि क्षेत्र को अग्रिम <b>Advances to Agriculture</b>	9032	9188
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम <b>Advances to Micro and Small Enterprises</b>	6478	8127
निर्यात वित्त <b>Export Finance</b>	1931	2334
शाखाओं की कुल संख्या <b>Total number of branches</b>	950	1037
कर्मचारियों की संख्या <b>Number of Employees</b>	12866	12831
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय <b>Average Business per Employee</b>	8.27	9.00
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) <b>Net Profit per Employee (₹ in lakh)</b>	5.42	5.91

## निदेशक मण्डल (31 मार्च, 2013 को)

## BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31<sup>st</sup> March, 2013)

<b>श्री प्रतीप चौधरी</b> अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मेडम कामा रोड, मुम्बई - 400 021	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन पदेन अध्यक्ष	<b>Shri Pratip Chaudhuri</b> Chairman State Bank of India, Corporate Centre Madame Cama Road, Mumbai-400021	Chairman, ex-officio under clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
<b>श्री बी. श्रीराम</b> प्रबन्ध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर 302005	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन मनोनीत	<b>Shri B. Sriram</b> Managing Director State Bank of Bikaner and Jaipur Head Office, Tilak Marg Jaipur - 302 005	Nominated under clause (aa) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्रीमती माल्विका सिन्हा</b> मुख्य महाप्रबन्धक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं विदेशी विनिमय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक नई दिल्ली	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Smt Malvika Sinha</b> Chief General Manager, Deptt of Non-Banking Supervision, Issue Deptt and Foreign Exchange Deptt, Reserve Bank of India, New Delhi	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री राजीव एन. मेहरा</b> मुख्य महाप्रबन्धक, (ए एवं एस), भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई - 400 021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Shri Rajeew N. Mehra</b> Chief General Manager (A & S) State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai-400021	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री प्रदीप कुमार सान्याल</b> उप महाप्रबन्धक, (ए एवं एस), सहयोगी बैंक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर मुम्बई - 400 021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Shri Pradip Kumar Sanyal</b> Dy. General Manager (A&S) Associate Banks Department State Bank of India Corporate Centre, Mumbai-400021	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री राजेश टी. मनुबरवाला</b> 9, अमीजाधव बंगला आशिष होटल के पास, एसबीसी चौकड़ी भरूच - 392001	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Shri Rajesh T. Manubarwala</b> 9, Amijadav Bunglows, Near Hotel Ashish, ABC Chokdi, Bharuch -392001	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री भारत रतन</b> बी. रतन एण्ड एसोसियेट्स दुकान सं. 408-409, महक टावर, कैलाश सिनेमा रोड, सिविल लाइस, लूथियाना - 141001	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Shri Bharat Rattan</b> B. Rattan & Associates, Shop No. 408-409, Mahak Tower, Kailash Cinema Road, Civil Lines Ludhiana-141001	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री अरुण कुमार सराफ</b> प्रबन्ध निदेशक, ज्यूनियर होटलस् प्रा. लि., ग्रांड हयात मुम्बई, शान्ताक्रूज मुम्बई - 400 005	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन चयनित निदेशक	<b>Shri Arun K Saraf</b> Managing Director,, Juniper Hotels Pvt Ltd., Grand Hyatt Mumbai, Santacruz, MUMBAI-400005	Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री कुणाल डालमिया</b> लिनडसे टॉवर, नवम तल, 13, नेलीसेन गुप्ता सारनी, कोलकाता-700087	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत	<b>Shri Kunal Dalmia</b> Lindsay Tower, 9th Floor, 13, Nelisen Gupta Sarnee, Kolkata-700087	Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act
<b>श्री मिहिर कुमार</b> निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) तृतीय तल, जीवन द्वीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत	<b>Shri Mihir Kumar</b> Director, Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services (Banking Division), 3rd Floor, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi.-110001	Nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
<b>श्री सुनील दत्त बाली</b> 'मुस्कान' 4/83 विद्याधर नगर, जयपुर	अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीबी) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत	<b>Shri Sunil Dutt Bali</b> Muskan, 4/83, Vidhyadhar Nagar, Jaipur	Nominated by the Central Government under clause (cb) of sub-section (1) of section 25 read with sub section (2A) of section 26 of the Act.
<b>श्री डी.के. जैन</b> एवल खिडकी परिचालक स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर अं.का. पटेल सर्किल उदयपुर - 313001	अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीए) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत	<b>Shri D.K. Jain,</b> S. W. O. State Bank of Bikaner & Jaipur, Z. O., Patel circle, Udaipur-313001	Nominated by the Central Government under clause (ca) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (2A) of section 26 of the Act.

निदेशक मण्डल ( 31 मार्च 2013 को )  
**BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31<sup>st</sup> March, 2013)**

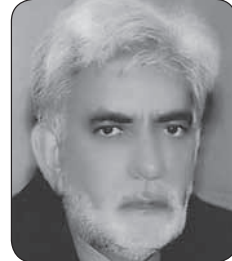
---



श्री प्रतीप चौधरी  
अध्यक्ष  
**Shri Pratip Chaudhuri**  
*Chairman*



श्री बी. श्रीराम  
प्रबन्ध निदेशक  
**Shri B. Sriram**  
*Managing Director*



श्री राजीव एन मेहरा  
**Shri Rajeev N Mehra**



श्री प्रदीप कुमार सान्याल  
**Shri Pradip Kumar Sanyal**



श्रीमती माल्विका सिन्हा  
**Smt. Malvika Sinha**



श्री मिहिर कुमार  
**Shri Mihir Kumar**



श्री राजेश टी.मनुबरवाला  
**Shri Rajesh T. Manubarwala**



श्री भारत रतन  
**Shri Bharat Rattan**



श्री कुनाल डालमिया  
**Shri Kunal Dalmia**



श्री अरुण के. सराफ  
**Shri Arun K. Saraf**



श्री एस.डी. बाली  
**Shri S.D. Bali**



श्री डी.के. जैन  
**Shri D.K. Jain**

**भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम, 1959 की धारा 43( 1 )  
के निबन्धनों के तहत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं  
भारत सरकार को निदेशक मंडल का प्रतिवेदन**

**प्रतिवेदन की अवधि: 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013**

स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक मंडल को बैंक के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खातों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

## **प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण**

### **आर्थिक परिदृश्य**

#### **वैश्विक अर्थव्यवस्था**

वैश्विक अर्थ व्यवस्था में सुधार आया है किंतु उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं में सुधार का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, वर्ष 2013 के दूसरे भाग से धीरे-धीरे सुधार होना अपेक्षित है। बीते 6 महीनों में, विकसित आर्थिक नीति निर्माताओं ने अल्प अवधि की दो सबसे बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की है जो यूरो क्षेत्र ब्रेक अप की चुनौती एवं संयुक्त राज्य में फिस्कल क्लिक राज्य कोषीय समुचन से संबंधित हैं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजारों में व्यापक सुधार हुए हैं। बहुत सी उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कुछ वापसी हुई है। ब्रिक्स देशों ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रिका में वृद्धि हुई है। जबकि चीन, रूस एवं भारत में यह नीचे रही। विकसित देशों में मुद्रास्फीति के आंकड़े नियंत्रण में रहे। उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति ने एक मिश्रित चित्रण प्रस्तुत किया। मुद्रास्फीति ब्राजील, रूस तथा टर्की में बढ़ी जबकि चीन, कोरिया, थाइलैंड और चिली में यह कम रही।

## **भारतीय अर्थव्यवस्था**

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में अग्रिम अनुमानित 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर जनवरी 2013 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत तीसरी तिमाही के आधार रेखीय अनुमानों के अनुसार वृद्धि दर की तुलना में कम रही जो उद्योग व सेवा क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि से धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गत वर्ष की तुलना में कुछ सुधार की आशा है। औद्योगिक गतिविधि नए निवेश में कमी आने तथा परियोजनाओं में आ रहे गतिरोधों तथा क्रियान्वयन नहीं होने के कारण धीमी रहने की आशा है।

मार्च 2013 तक, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के सूचक अनुमान 6.8 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 6.0 प्रतिशत रहा जिसका मुख्य कारण वर्ष के दूसरे भाग में अखाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में आई तेज गिरावट हैं। घरेलू मांग-आपूर्ति संतुलन, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों का परिदृश्य एवं सामान्य मानसून की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्ष 2013-14 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत की विस्तार सीमा में रहने की आशा है।

## **राजस्थान की अर्थव्यवस्था**

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन आधारित है। अकाल एवं सूखे

की समस्या का राजस्थान की अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। 2001 की जनगणना के अनुसार 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए सूखे एवं अकाल के समग्र सर्वाधिक प्रभावित कृषक आदिवासी ही होते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण, कानून एवं व्यवस्था की बेहतर स्थिति, उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं, निवेश उन्मुख वातावरण, एवं अत्यल्प जनसंख्या घनत्व होने के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद राजस्थान, निवेश आकर्षित करने में भारत में अग्रणी है। एनसीआर से जुड़े क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी में ऑटोमोबाइल तथा विनिर्माण कंपनियां आ रही हैं। भारत में खदान एवं खनन के क्षेत्र में राजस्थान अधिक महत्वपूर्ण है। यह राज्य सीमेंट के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां सांभर में नमक के भंडार हैं, खेतड़ी में तांबे की खाने तथा दरीबों एवं जावर में जस्ते की खाने हैं।

प्राकृतिक सुंदरता एवं महान इतिहास के कारण राजस्थान में पर्यटन एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें तथा जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर के रेगिस्तानी किले पर्यटकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थान हैं। पर्यटन के कारण हथकरघा उद्योग विकसित हुआ है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में राजस्थान सरकार एवं एचपीसीएल के बीच राजस्थान के बाड़मेर में 9 एमएमटीपीए रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।



**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE STATE BANK OF INDIA,  
THE RESERVE BANK OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF INDIA  
IN TERMS OF SECTION 43(1) OF THE STATE BANK OF INDIA  
(SUBSIDIARY BANKS) ACT 1959**

**PERIOD COVERED BY THE REPORT: 1<sup>ST</sup> APRIL 2012 TO 31<sup>ST</sup> MARCH 2013**

The Board of Directors of State Bank of Bikaner and Jaipur have pleasure in presenting this Annual Report together with the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2013.

## **MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS**

### **ECONOMIC ENVIRONMENT**

#### **WORLD ECONOMY**

Global economic prospects have improved but the road to recovery in the advanced economies will remain bumpy. In advanced economies, activity is expected to gradually accelerate, starting in the second half of 2013. Over the past six months, advanced economy policymakers have successfully defused two of the biggest short-term threats to the global recovery, the threat of a euro area breakup and a sharp fiscal contraction in the United States caused by a plunge off the "fiscal cliff." In response, financial markets have rallied on a broad front. Growth in several emerging and developing economies (EDEs) rebounded from the moderation. Among BRICS countries growth accelerated in Brazil and South Africa, while it persisted below trend in China, Russia and India. Inflation has remained benign in the Advanced Economies in the absence of demand pressures and inflation expressions remain well anchored. The inflation in EDEs present a mixed picture. While inflation has picked up in Brazil, Russia and Turkey, it has eased in China,

Korea, Thailand and Chile.

#### **INDIAN ECONOMY**

Central Statistical Organisation's (CSOs) advance estimate of 5.0 per cent GDP growth during financial year 2012-13 is lower than the Reserve Bank's base line projections of 5.5 per cent set out in the Third Quarter Review of January, 2013 reflecting slower than expected growth in both industry and services. During 2013-14 economic activity is expected to show modest improvement over last year. The out look for industrial activity remains subdued, with the pipeline of new investment drying up and existing projects stalled by bottlenecks and implementation gaps. The RBI has projected baseline GDP growth for financial year 2013-14 at 5.7 per cent.

By March, 2013, WPI inflation at 6.0 per cent turned out to be lower than the Reserve Banks of India's indicative projection of 6.8 per cent mainly due to sharp decline in non-food manufactured product inflation in the second half of the year. Keeping in view the domestic demand - supply balance, the outlook for global commodity prices and the forecasting a normal monsoon, RBI expects WPI inflation to be in range band around 5.5 per cent during 2013-14.

#### **RAJASTHAN ECONOMY**

Rajasthan's economy is primarily agricultural and pastoral. The problem of famine and drought is deeply related with the economy of Rajasthan. According to the population of 2001 about 80% of the population lives in rural areas therefore agriculturist tribes



माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार श्री पी. चिदम्बरम  
बैंक की 1000वीं शाखा सांभर का ऑन-लाईन उद्घाटन  
करते हुए

On-line Inauguration of 1000<sup>th</sup> Branch of the  
Bank at Sambhar by Hon'ble Union Finance  
Minister, Govt. of India Sh. P. Chidambaram

## वित्तीय क्षेत्र में विकास

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों में तेज गिरावट का रूख रहा है जबकि जमाओं में वृद्धि शिथिल रही। मार्च 2013 के अंत में, वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशियों एवं अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर गत वर्ष क्रमशः 17.4 प्रतिशत एवं 19.3 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 13.2 प्रतिशत तथा 13.9 प्रतिशत रही।

वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि दर में कमी बढ़ती मुद्रास्फीति और दोहरे घाटे के जोखिम के कारण और इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर वृद्धि को धीमा करने के खतरे को बढ़ा दिया। गतिरोधों के बीच मौद्रिक नीति द्वारा बढ़ते वृद्धि, के खतरों को समझा और धीमी होती वृद्धि दर को ध्यान में रखने से मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी हुई। सरकार ने वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही में ठोस कार्यनीति और सुधार प्रारंभ किए। इन सुधारों के पूर्ण कार्यान्वयन से वर्ष 2013-14 में धीमी होती वृद्धि दर पर लगाम लगाने एवं इसमें सुधार होने की आशा है। नीति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां

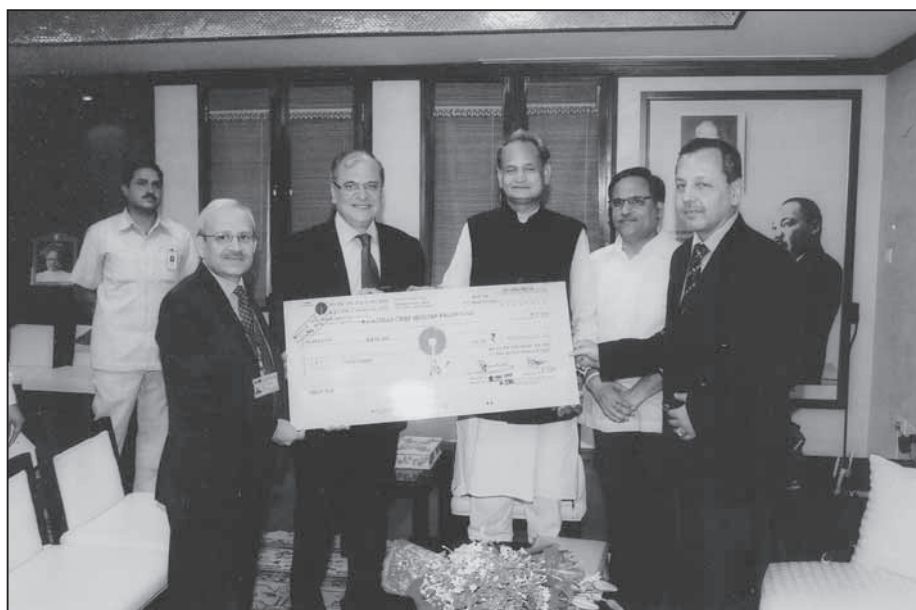
- ₹15 लाख तक के आवास ऋण जिनकी लागत ₹25 लाख से अधिक नहीं होने पर 1 प्रतिशत की सरकारी ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।
- छोटे वैयक्तिक निवेशकों को शेयरों, म्यूचुअल फंड तथा अन्य सुरक्षा निधियों में लेन देन हेतु ₹50000 की शेष, सीमा सहित बिना किसी वार्षिक अनुरक्षण प्रभार के नो फ्रिल डी-मैट खाते खोले जाएंगे साथ ही यदि पोर्टफोलियो की राशि ₹2 लाख तक है तो अधिकतम शुल्क ₹100 प्रति वर्ष की दर से लिया जाएगा।
- बेसल III पर भारतीय बैंकों को अंतिम दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी कर दिए। बैंकों को इन मानकों

का अनुपालन अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के बीच करना होगा।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अस्थिर दर वाले आवास ऋणों के पूर्व भुगतान प्रभार को समाप्त कर दें। इससे वर्तमान और नए उधारकर्ताओं के बीच भेदभाव समाप्त होगा। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा से आवास ऋणों पर अस्थिर दरों में कमी आएगी।
- वित्तीय समावेशन में बैंकों को केंद्रीय भूमिका निभानी है। उन्हें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोले गए खातों के लेन देन पर ध्यान केंद्रित करना है एवं अर्थ पूर्ण वित्तीय समावेश सिर्फ बैंक ही उत्पादों की समस्त श्रृंखला उपलब्ध करा सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण केंद्रों पर सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि हेतु आउटलेट खोलने की अनुमति बैंकों को प्रदान कर दी है।
- ऋण का भुगतान करने हेतु सभी उपभोक्ताओं को नेफ्ट (एनईएफटी)

सुविधा का उपभोग करने की अनुमति प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया है।

- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी, के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधारी सीमा को उनके निवल मांग और आवधिक देयताओं के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।
- लघु अवधि के फसली ऋण हेतु सरकारी ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी।
- 01/04/2013 से 31/03/2015 तक की अवधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी पर ₹100 करोड़ या इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को निवेश के 15 प्रतिशत का निवेश भत्ता कटौती करने की पात्रता होगी।
- डिसकोम्स के वित्तीय पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय पुनर्गठन योजना तैयार करें, शीघ्र ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें एवं योजना का लाभ उठाएं।



बैंक द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ की सहायता प्रदान की गई

Bank Donated Rs. 2 crore towards Rajasthan Chief Minister's Relief Fund for Relief Measures



are the biggest sufferers in time of famine and drought. Rajasthan is the leading investment destination in India after Maharashtra and Gujarat because of peaceful environment, better law and order situation, excellent infrastructure, investment friendly climate and very less population density. Areas facing NCR such as Bhiwadi are now buzzing with automobile and manufacturing companies. Rajasthan is pre-eminent in quarrying and mining in India. The state is the second largest source of cement. It has rich salt deposits at Sambhar, copper mines at Khetri and zinc mines at Dariba and Zawar.

Endowed with natural beauty and a great history, tourism is flourishing in Rajasthan. The palaces of Jaipur, lakes of Udaipur and desert forts of Jodhpur, Bikaner & Jaisalmer are among the most preferred destination of many tourists, Indian and foreign. A spin-off of tourism has been the growth of the handicrafts industry. Tourism provides a big boost to the economy of Rajasthan. Recently HPCL signs a MoU with Rajasthan Government for 9MMTPA Refinery-cum-Petrochemical Complex at Barmer in Rajasthan.

## **DEVELOPMENTS IN THE FINANCIAL SECTOR**

The year 2012-13 witnessed a sharp decline in the advances growth of scheduled commercial banks (SCBs) while deposit growth also subdued. The year-on-year aggregate deposits and advances growth of SCBs stood at 13.2% and 13.9% respectively as at end-March 2013, compared to 17.4% and 19.3% respectively during the previous year.

Growth slowdown, persistent inflation and the twin deficit risks came to the fore during 2012-13 and enervated the Indian economy endangering the reversal of its declining growth path.

Amidst trade-offs, monetary policy factored in increased growth risks and shifted its stance to calibrated easing to address the growth slow down as headline inflation gradually moderated. The Government also launched concerted policy action and reforms during H2 of 2012-13. These reforms, with fuller implementation, are expected to arrest the downward spiral and kick in the modest recovery in 2013-14. Some of the important policy developments:

- Interest subvention of 1 per cent on housing loans extended to loans upto ₹15 lakh, where cost of the house does not exceed to ₹25 lakh.
- Small individual investors will get no-frills demat accounts for trading in stocks, mutual funds and other securities without any annual maintenance charges for holdings up to ₹50000. Also, the charges would be capped at a maximum of ₹100 a year if the portfolio value is up to ₹2 lakh.
- RBI released the final guidelines for Indian Banks on BASEL-III. Banks will have to comply with these norms between April, 2013 and March, 2018.
- RBI has notified Banks to obliterate the foreclosure charges (prepayment charges) on floating rate home loans. This will lead to reduction in the discrimination between existing and new borrower; and competition among banks will result in finer pricing of floating rate home loan.
- The central role in financial inclusion has to be played by banks. They need to focus on transactions in accounts opened under financial inclusion. Only

banks can offer the entire suite of products required to usher in meaningful financial inclusion.

- RBI has allowed Banks to establish outlet for BCs in rural centres to boost the Government's financial inclusion programme.
- RBI has advised all Banks to allow their customers to use the National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility for repaying loans.
- The borrowing limit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) under the Marginal Standing Facility (MSF) raised from 1% to 2% of their Net Demand and Time Liabilities.
- Interest Subvention scheme for short-term crop loan to be continued.
- Companies investing ₹100 crore or more in plant and machinery during the period 01.04.2013 to 31.03.2015 will be entitled to deduct an investment allowance of 15% of the investment.
- Guidelines regarding financial restructuring of DISCOMS have been announced. State Government urged to prepare the financial restructuring plan, quickly sign MoU and take advantage of the scheme.
- Additional deduction of interest up to ₹1.00 lac for a person taking first home loan up to ₹25.00 lac during period 01.04.2013 to 31.03.2014.
- All Branches of Public Sector Banks to have ATM by 31.03.2014.
- Proposal to set up India's first women's Bank as a Public Sector Bank.

- 01/04/2013 से 31/03/2014 की अवधि के दौरान ₹25 लाख तक का प्रथम गृह ऋण लेने वाले व्यक्ति को ब्याज में एक लाख तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा।
- 31/03/2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्त शाखाओं के पास एटीएम होगा।
- भारत के प्रथम महिला बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## संभावनाएं, चुनौतियां एवं परिदृश्य :

केंद्रीय बजट 2013-14 में वर्ष 2013-14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया है जिससे बैंकिंग प्रणाली में साख एवं अन्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की आशा है। बड़ी परियोजनाओं के धीमी गति से प्रगति की समस्या से पार पाने के लिए निवेश हेतु कैबिनेट निवेश समिति की स्थापना की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत निहित रहा एवं वर्ष 2013-14 के लिए यह 4.8 प्रतिशत अनुमानित है।

बैंक के समक्ष राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बाजार अंश में सुधार करने सहित, अस्ति गुणवत्ता बनाए रखने, व्यवसाय एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक का अनुकूलतम उपयोग, परिष्कृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विकास, निवल ब्याज अंतर में वृद्धि, गैर कोषीय व्यवसाय का व्यापक विस्तार एवं उच्च स्तरीय कॉरपोरेट अभिशासन व्यवहार का अभिग्रहण कर ग्राहक सेवाओं में और सुधार करने पर जोर देने की प्रमुख चुनौतियां निरंतर बनी हुई हैं।

## निगमित परिचालन

### व्यवसाय निष्पादन

बैंक का समग्र व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं सकल अग्रिम) ₹19032 करोड़

(17.06 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए अन्त-मार्च 2013 को ₹130590 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है, जो कि अन्त-मार्च 2012 को ₹111558 करोड़ था। कुल जमाराशियाँ अन्त-मार्च 2013 तक ₹10544 करोड़ (17.12 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹72116 करोड़ के स्तर पर जा पहुँची है, जबकि सकल अग्रिम ₹8489 (16.98 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए अंत मार्च 2013 को ₹58474 करोड़ के स्तर तक पहुँच गये हैं। जमाराशियों की लागत वर्ष 2011-12 की 6.85 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 7.13 प्रतिशत हो गई है, जबकि अग्रिमों पर आय सुधर कर 11.51 प्रतिशत से 11.64 प्रतिशत हो गई।

## कोष एवं निवेश

चालू वित्त वर्ष में वृद्धि में कमी आई है और महंगाई दर रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तर से ऊपर बनी रही है। मौद्रिक नीति ने इस बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति दर का सामना सधे हुए उपायों से किया है। वर्ष के प्रारम्भ में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2012 में अपनी रेपो दर में 50 आधार बिन्दुओं की कमी की। चाहे 2012 के बाद से बढ़ती मुद्रा स्फीति और दोहरे घाटे के चलते नीतिगत दरों को और अधिक सरल करने की संभावना को सीमित कर दिया हो, उत्पादक क्षेत्रों में साख-अभियोजन में वृद्धि हेतु पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने हेतु विकास को सहारा देने के लिए अनुवर्ती उपाय किये गये। तरलता प्रबंधन उपायों के अन्तर्गत मौद्रिक एवं तरलता परिस्थितियों में सुधार के लिए दो चरणों में नकद आरक्षी अनुपात में 50 आधार बिन्दुओं की कटौती। साथ ही साख की स्थिति में सुधार के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात भी कम किया गया। आगे, दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) के माध्यम से तरलता आपूर्ति के अलावा रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष खुले बाजार कार्यकलापों के अन्तर्गत नीलामी सक्रिय

उपयोग किया एवं लगभग ₹1.3 ट्रिलियन की प्रारंभिक तरलता उपलब्ध करवाई। दोनों उपायों का विवेकपूर्ण उपयोग अर्थात् अप्रैल से दिसंबर तक अपरिवर्तनीय नीति-दर और अग्रिम सरलीकरण उपायों से दोहरा लाभ हुआ जो कि मुद्रा-स्फीति उच्चतम स्तर से धीरे-धीरे नीचे आने एवं नवम्बर तथा दिसंबर 2012 में साख की मांग में सुधार होने के संकेतों से परिलक्षित हुआ। तथापि मुद्रा स्फीति रिजर्व बैंक के सहज स्तर से ऊपर बनी रही।

2012-13 में मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा में रेपो रेट में 25 आधार बिन्दुओं की कमी कर इसे 8.00 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया और अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) में भी 25 आधार बिन्दुओं की कमी कर इसे उनकी निवल मांग एवं आवधिक देयताओं को 4.25 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत कर दिया गया। इसे जारी रखते हुए मार्च 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में पुनः 25 आधार बिन्दुओं की कमी कर इसे 7.5 प्रतिशत कर दिया।

अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में 10 वर्षीय बैंचमार्क प्रतिभूति पर आय 8.74 प्रतिशत से कम होकर 8.12 प्रतिशत हो गई तथापि सावधिक तरलता अनुपात में कमी होने के परिणाम स्वरूप अगस्त में आय दिखने लगी। सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों तथा तत्पश्चात रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती और खुले बाजार क्रियाकलापों की घोषणा से 10 वर्षीय बैंचमार्क प्रतिभूति पर आय में और कमी आई और यह 7.78 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। इसने हमें सरकारी प्रतिभूतियों को भुनाने का अवसर प्रदान किया।

गार एवं एस एंड पी द्वारा भारत पर नकारात्मक दृष्टिकोण और यूरोजोन पर बढ़ती चिंताओं जैसे मुद्दों के कारण वर्ष की प्रथम तिमाही में शेयर बाजार मुख्यतः लाल निशान में रहा। तथापि, दूसरी एवं तीसरी तिमाही में सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों